केवल विभागीय प्रयोगार्थ

महेन्द्र रंगा
MAHENDRA RANGA
मुख्य आयुक्त
CHIEF COMMISSIONER

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
मुख्य आयुक्त कार्यालय
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
जयपुर

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
CGST & CENTRAL EXCISE
Jaipur

10 जुलाई, 2024
D.O. No. GCCO/TECH/MISC/440/2023

प्रिय साथियों,

'संवाद': जुलाई, 2024

1 जुलाई, 2024 को भारत में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की सातवीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में जीएसटी की शुरुआत ने देश की कर प्रणाली को बदलकर, करों को सरल और एकीकृत करके एकल प्रणाली बना दिया और एकल बाजार की अवधारणा को सक्षम बनाया। हितधारकों, विशेष रूप से कर पेशेवरों के सहयोगात्मक प्रयासों ने एक सहज परिवर्तन सुनिश्चित किया। जीएसटी परिषद ने विकसित होती जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनों को अनुकूलित करने में काफी सक्रियता दिखाई है, जो हमारे लोकतंत्र की जीवंतता और भारत में फलते-फूलते सहकारी संघवाद को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रणालियों को सक्रिय रूप से विकसित करना होगा।

2. हमने बहुत उत्साह के साथ 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया। इस अवसर पर 22 अधिकारियों को उनकी कड़ी मेहनत और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। जोन के शीर्ष 20 करदाताओं का भी अभिनंदन किया गया। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री माननीय डॉ. प्रेम चंद बैरवा और विशिष्ट अतिथि श्री रवि प्रकाश मेहरड़ा, महानिदेशक, एसीबी, राजस्थान की गरिमामयी उपस्थिति में सांयकाल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 'कथक धरोहर' द्वारा 'एकात्म' प्रस्तुति के द्वारा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों के माध्यम से एक एकीकृत सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन के रूप में बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर "जीएसटी के सात वर्ष" नामक एक पत्रिका का भी विमोचन किया गया, जिसमें मुख्यतः 'विकसित भारत के लिए जीएसटी वास्तुकला और 'जीएसटी के सात वर्ष - मुद्दे और चुनौतियाँ' विषयों पर लेख शामिल हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद।

केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005
Off. : 0141-2385155, Fax : 0141-2385130, e-mail : ccu-cexjpr@nic.in, Twitter Handle : @CGSTJAIPURZONE

3. जून, 2024 माह का राजस्व जून, 2023 माह के राजस्व की तुलना में 18% अधिक है। 7.7% की अखिल भारतीय वृद्धि दर की तुलना में यह काफी अनुकूल लगता है। हमारे विभाग तथा राज्य कर विभाग द्वारा चलाए गये अभियान, बेईमान ऑपरेटरों के प्रवेश को रोकने और उन्हें हटाने तथा अन्य प्रवर्तन उपायों ने इसमें योगदान दिया है।

4. मुख्य आयुक्त कार्यालय में स्थित केंद्रीय आसूचना इकाई (सीआईयू) ने महत्वपूर्ण कर चोरी के मामलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो BIFA और ADVAIT जैसे डेटा एनालिटिक्स माध्यमों की उपयोगिता का प्रदर्शन करता है। सीआईयू द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी अलवर ने पाया कि मेसर्स वनवोल्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने छूट वाली आपूर्ति के संदर्भ में लिए गये आईटीसी को रिवर्स नहीं किया था। अब करदाता ने 1.53 करोड़ रुपये की आईटीसी को वापस कर दिया है। सीआईयू की सूचना पर सीजीएसटी जयपुर द्वारा दर्ज किए गए एक अन्य मामले में 1.17 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला है। यह पता चला है कि मेसर्स गेमिट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन गेमिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान कर रहा था और लेनदेन/ अंकित मूल्य पर 28% की दर से जीएसटी का भुगतान करने के बजाय कमीशन पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान कर रहा था।

5. सीजीएसटी जोधपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में 231 करोड़ रुपये की शुल्क चोरी का पता चला है। इस मामले में, सेवा प्राप्तकर्ता अर्थात मेसर्स SWML लिग्नाइट माइंस में खुदाई के लिए अपने ठेकेदारों को मुफ्त में डीजल उपलब्ध करा रहे थे। ठेकेदारों ने 1283 करोड़ रुपये की मुफ्त आपूर्ति की लागत को अपने कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया, जिसके कारण ठेकेदारों द्वारा 231 करोड़ रुपये की जीएसटी राशि का कम भुगतान किया गया। मेसर्स आरएआर इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सीजीएसटी जयपुर ने अवरुद्ध आईटीसी का गलत लाभ उठाने और जीएसटीआर-1 में घोषित आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान न करने के माध्यम से 1.06 करोड़ रुपये की चोरी का पता लगाया है। देयता को स्वीकार करते हुए करदाता ने अब तक 1.02 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

6. आयुक्तालयों द्वारा डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया गया। सीजीएसटी उदयपुर ने 20.53 करोड़ रुपये की जीएसटी राशि का भुगतान न करने का मामला दर्ज किया है। ADVAIT आंकडों के विश्लेषण से पता लगाया कि मेसर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मेसर्स उचित एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड को 114 करोड़ रुपये के भुगतान पर टीडीएस काटा गया था, लेकिन करदाता ने अपने रिटर्न में यह राशि घोषित नहीं की थी। भुगतान की रसीद और उस पर जीएसटी देयता को स्वीकार करते हुए करदाता ने 20.53 करोड़ रुपये की जीएसटी राशि जमा करवा दी है। ADVAIT और AIO पोर्टल का उपयोग करके दर्ज किए गए एक अन्य मामले में सीजीएसटी उदयपुर ने एक गैर-मौजूद फर्म अर्थात मेसर्स अजीत एंटरप्राइजेज की पहचान की, जिसने फर्जी इनवॉइसिस पर 2.61 करोड़ रुपये की आईटीसी का लाभ उठाया और 4.98 करोड़ रुपये का आईटीसी पारित किया।

7. डीजीजीआई, जयपुर भी कर चोरी का पता लगाने में काफी सक्रिय रहा है। पहले मामले में, उदयपुर में दो संबंधित स्वामित्व वाली फर्मों, मेसर्स द रॉयल रिट्रीट, उदयपुर, जो आवास और इवेंट सेवाएं प्रदान करती है, और इनकी संबंधित मेसर्स WDNE, उदयपुर, जो एक इवेंट मैनेजमेंट सेवा प्रदाता है, ने अपने जीएसटी रिटर्न में गंतव्य शादियों और कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के आयोजन के संदर्भ में प्राप्त नकद भुगतान को शामिल नहीं किया था, जिससे 6.47 करोड़ रुपये की जीएसटी की चोरी का पता चला। दोनों फर्मों के मालिकों ने चोरी को स्वीकार करते हुए अपनी देनदारी के लिए 2.14 करोड़ रुपये का प्रारंभिक भुगतान भी कर दिया है। एक अन्य मामले में उन्होंने 353 फर्जी फर्मों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश करके बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के बिना 694 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी पारित की गई है। एक संदिग्ध करदाता के बैंक खाते की जांच से वित्तीय लेनदेन का एक जटिल जाल सामने आया, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली का फायदा उठाने के लिए तैयार किया गया था। अपराधी द्वारा फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं और उनका इस्तेमाल कई बैंक खातों के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के लिए किया था तथा अंततः बड़ी मात्रा में नकदी निकाल ली गयी थी। कार्यप्रणाली में चालू खाते खोलने के लिए एपीएमसी लाइसेंस का दुरुपयोग भी शामिल था। दो सूत्रधारों (मास्टरमाइंड) को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा एक ऐसे बैक ऑफिस की भी पहचान की गई जहां लाभार्थियों को लौटाने के लिए नकदी जमा की जा रही थी। ठिकाने की तलाशी में 2.42 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद हुई है। यह मामला वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए परिष्कृत तरीकों को उजागर करता है।

8. जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में व्यापार सुविधा बढ़ाने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें जारी की गईं हैं। उल्लेखनीय रूप से, परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कुछ मामलों में ब्याज और शास्ति माफ करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि मांगे गए पूरे कर का भुगतान 31 मार्च, 2025 तक किया जाए। इसके अतिरिक्त, परिषद ने मुनाफाखोरी विरोधी नए आवेदनों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से एक सावधि विधि खंड (sunset clause) का सुझाव दिया। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग द्वारा अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। इसके अलावा, परिषद ने जीएसटी के तहत अपील दायर करने के लिए आवश्यक पूर्व-जमा की मात्रा में कमी और सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए अधिसूचित तिथि से तीन महीने की अवधि प्रदान करने की सिफारिश की। एक नई धारा 74A भी शामिल की गयी है। इन उपायों से व्यापार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा, जो व्यवसाय को आसान बनाने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए ठोस प्रयास को प्रतिबिंबित करेगा।

9. भारत में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) नामक नए आपराधिक कानूनों की शुरूआत देश के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। ये कानून, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे, का उद्देश्य न्याय प्रणाली को

आधुनिक बनाना और इसे अधिक न्यायोन्मुखी बनाना है। हालाँकि ये कानून मुख्य रूप से आपराधिक न्याय को संबोधित करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कराधान पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। हमें विशेष रूप से डिजिटल साक्ष्य के क्षेत्र में नई आवश्यकताओं के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है।

10. हमारे सेवानिवृत्त अधिकारियों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा के लिए पेंशन लाभ का समय पर वितरण आवश्यक है। हमने पेंशन मामलों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए 11.06.2024 को कार्यालय आदेश संख्या 10/2024 के माध्यम से एक SOP जारी की है। SOP में पेंशन मार्गदर्शक मंडल और पेंशन मित्र भी बनाए गए हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का लाभकारी उपयोग करने की मांग की गई है। सभी आयुक्तों को SOP का पालन करने की आवश्यकता है। मुख्य आयुक्त कार्यालय स्तर पर इसकी नियमित निगरानी की जाएगी।

11. भारतीय क्रिकेट टीम ने लंबे अंतराल के बाद विश्व कप जीता है। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और टीम वर्क की वजह से संभव हुआ है। अगर हम व्यक्तिगत गौरव के बजाय टीम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो शानदार नतीजे सामने आएंगे। हमें इस जीत से टीम वर्क के मूल्यों को सीखना और अपनाना चाहिए।

12. 21 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। इस दिन, जोन के सभी आयुक्तालयों के अधिकारियों ने सपरिवार सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। ऐसे आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि प्रतिभागियों के बीच एकता और शांति की भावना भी बढ़ाते हैं।

13. इस माह के 'ज्ञान संग्रह' अंक में निम्नलिखित दो सारगर्भित आलेख सम्मिलित किए गए हैं:-

(क) *A critical analysis of refund under inverted duty structure – A case study* – लेखक: श्री महेश कुमार अचरा, अधीक्षक, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर; एवं,

(ख) *Interception of conveyance in transit under Section 129 of the CGST Act, 2017 – Applicability of Section 130 of the CGST Act, 2017* - लेखक: श्री देवी दत्त शर्मा, अधीक्षक, सीजीएसटी सम्भाग-ई, बहरोड।

उपरोक्त अधिकारियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद।

14. जैसे एक अध्याय में सूर्यास्त होता है, वैसे ही दूसरे अध्याय में उदय होता है। हम श्री रामजी लाल मीना, आयुक्त को जोन से सेवानिवृत्त होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमें उनकी कमी बहुत खलेगी। इसके अतिरिक्त, हम श्री सुरेश मीना, सहायक आयुक्त, श्री गुलाब चंद मीना, सहायक आयुक्त, श्री हरि नारायण कोली, अधीक्षक, श्री जगदीश नारायण कोली, अधीक्षक, श्री करण सिंह, वाहन चालक, श्री राजू लाल खींची, हेड हवलदार और श्री भंवर सिंह, एमटीएस को भी शुभकामनाएं देते हैं, जो पिछले माह में सेवानिवृत्त हुए हैं। हम उन्हें भावभीनी विदाई देते हैं और आशा करते हैं कि उनका भविष्य खुशियों और रोमांचक अवसरों से भरा हो।

15. भीषण गर्मी के बाद मानसून ने बहुत राहत दी है। मानसून की बारिश ने शुष्क भूमि को भिगो दिया है, बारिश से भीगी मिट्टी की खुशबू के साथ स्कूल के दिनों की यादें जीवंत हो उठी हैं। मैं अपने स्कूल के दिनों की यादों से एक कविता के साथ समापन करना चाहता हूँ:-

उमड घुमड कर आये बादल। शोख घटा बन छाये बादल।
इक बदली मदिरा छलकाए, मन का प्याला भरता जाये,
मय बरसाते आये बादल। उमड घुमड कर आये बादल।
बुझी प्यास धरती है लहकी, डॉल डॉल गुलशन की महकी,
हरसू प्यास बुझाये बादल। उमड घुमड कर आये बादल।
लगी झूमने हर इक वादी, चली है पुरवा भी मदमाती,
धुन मल्हार सुनाये बादल। उमड घुमड कर आये बादल।
बरसे है सावन की बदली, चले नार ज्यूं ढलकी ढलकी,
छम छम, छम छम आये बादल। उमड घुमड कर आये बादल।

अगले माह तक,

आपका शुभेच्छु

(महेंद्र रंगा)
मुख्य आयुक्त

सेवा में:- टीम जयपुर जोन।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

(i) ओएसडी, अध्यक्ष, सीबीआईसी, नई दिल्ली।

(ii) निजी सचिव, सदस्य (जीएसटी/सीई/एसटी एवं क्षेत्रीय प्रभारी), सीबीआईसी, नई दिल्ली।

(iii) मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर

(iv) प्रधान एडीजी, नासिन /डीजीजीआई, जयपुर

ज्ञान संग्रह

जुलाई, 2024

GYAN SANGRAH

JULY, 2024

A Critical Analysis of Refunds under Inverted Duty Structure – A case study

By – Mahesh Kumar Achra, Superintendent,
CGST & CX, Jaipur

Before I write upon above issue, I shall congratulate all CGST officers on successful completion of 7 years of GST on 1st July, 2024 and also offer my gratitude to higher officers for grand organization of celebrations on this occasion.

One of the major objectives of introducing "One Nation One Tax" structure called GST is to avoid the cascading effect of taxes. This anomaly was cured by the advent of a unified GST regime with effect from 1 July 2017. However, with the different tax rates made applicable for various goods & services, there arose a scenario where ITC gets accumulated without being fully utilized towards output taxes. Such accumulation is a result of defined pattern wherever it is due to rate of tax on input goods or services being higher than the rate of tax on output goods and services. The government has formulated a mechanism for refund of ITC accumulated when the rate of tax on the inputs being higher than the rate of tax applicable on the outward supply of goods and services. It was seen that credit accumulation on account of unutilized ITC can result in higher tax costs to businesses and a rise in the hidden tax cost for consumers. Governments have sought to address this issue in one way by envisaging to allow refund of ITC under Inverted Duty Structure under Section 54 of the Act.

Under CGST Act, 2017 the refund of inverted duty structure is being governed under Section 54(3)(ii) which is as under:-

> *"(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilized input tax credit at the end of any tax period:*
> *Provided that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in cases other than––;*
>
> ***(ii)*** ***where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies*** *(other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:"*

One of the case that has come into my notice is that a manufacturer of Cotton Yarn, Cotton blended yarn, Polyester/Viscose blended Yarn and Polyester/viscose Yarn chargeable to GST @ 0.1%, 5% and 12% is claiming refund of Accumulated ITC under Section 54(3) (ii) of CGST Act, 2017 under scheme of inverted duty structure. The manufacturer has inward supplies of raw materials/inputs chargeable to GST @ 5%, 12%, 18% and 28%. It is pertinent to mention here that the manufacturer has used all such inputs in manufacture and supply of goods chargeable to GST @ 0.1%, 5% and 12%. For brevity and clarity, the details of such outward supplies and inputs used in manufacture for outward supplies are enumerated as under:-

Description of Output supplies	Rate of GST on output supplies	Inputs utilized in manufacture of output supplies	Rate of GST applicable on inputs
Cotton Yarn	5%	Cotton	5%
		Packing material	12%
		Other inputs	28%
		Store consumables and spare	18%
Cotton blended yarn	5%	Cotton	5%
		Manmade fibre	18%
		Packing material	12%
		Other inputs	28%
		Store consumables and spares	18%
Polyster/Viscose blended Yarn	12%	Cotton	5%
		Manmade fibre	18%
		Packing material	12%
		Other inputs	28%
		Store consumables and spares	18%
Polyster/viscose Yarn	12%	Manmade fibre	18%
		Packing material	12%
		Other inputs	28%
		Store consumables and spares	18%
Other outward supply	0.1%	Cotton	5%
		Manmade fibre	18%
		Packing material	12%
		Other inputs	28%

The manufacturer of above goods has filed refund claim under Section 54(3)(ii) of CGST Act, 2017 by claiming refund as per formula under Rule 89(5) of CGST Rules, 2017 which is as under:-

Rule 89. Application for refund of tax, interest, penalty, fees or any other amount.-

(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula:-

Maximum Refund Amount = {(**Turnover of inverted rated supply of goods and services**) x Net ITC Adjusted Total Turnover} - [{**tax payable on such inverted rated supply of goods and services** x (Net ITC ÷ ITC availed on inputs and input services)}].

Explanation*:* - For the purposes of this sub-rule, the expressions -

(a) "Net ITC" shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and

(b) "Adjusted Total turnover" and "relevant period" shall have the same meaning as assigned to them in sub-rule (4).]

The Rule above has not defined and explained the **"Turnover of inverted rated supply of goods and services**" and so the manufacturer intended to have claimed the maximum amount of refund by taking the turnover of goods supplied at GST of one lower rates only.

The manufacturer has claimed the maximum refund amount by taking the **Turnover of inverted rated supply of goods chargeable to GST @ 0.1% and @5% only and thereby claimed higher amount of refund amount and encashed the accumulated ITC.**

In such cases the refund amount shall be calculated and allowed by taking the turnover of all goods supplied at @ 0.1%, @5% and 12% as mentioned in the table above. The refund sanctioning authority must be vigilant while allowing such refunds under inverted duty structure.

The CBIC has issued a master Circular No. 125/44/2019 – GST dated 18.11.2019 where in under Para 54 has explained the case of inverted duty structure by taking single outward supply only. The matter needs further clarifications when there are more than one outward supplies at different rates of GST as in the above case.

****

(The views are purely personal and for academic purpose only and shall not be having any legal impact)

Interception of conveyance in transit under Section 129 of the CGST Act, 2017 – Applicability of Section 130 of the CGST Act, 2017

By – Devi Dutt Sharma, Superintendent,
CGST Division-E, Behror

This is a case of a claim for refund of balance lying unutilised in Electronic Cash Ledger of a taxable person which led to the observation that goods cleared by the said taxable person,which were intercepted in transit without e-way bill,were released on payment ofpenalty equal to two hundred percent of tax payable bya temporary ID created for the purpose and, that too, without recovering the tax evaded by the said taxable person.

2. A claim for refund of unutilised balance of IGST (tax) amounting to Rs.69,230/- lying in the Electronic Cash Ledger was filed by **M/s Anushree Industries (Proprietor: Kritika Gupta having GSTIN 08DMWPG7237N1Z3)**vide FORM GST RFD-01 ARN AA080124092657Z dated 30.01.2024 showing the reason as "amount was mistakenly paid in this GSTIN but it was required to be paid to other GSTIN". However, no document was submitted in support of the claim.

3. In terms of CBIC Circular No. 125/44/2019-GST, dated 18..11.2019 and Instruction No. 03/2022-GST, dated 14.06.2022 it has to be ensured that the amount to be refunded is calculated in accordance with the provisions of section 49(6) of the CGST Act, 2017 which reads thus:-

> "(6) The balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provisions of section 54."

4.1. Though no arrear was pending recovery against the taxable person but on going through the task list of intimations in FORM GST DRC-03 it was observed that one DRC-03 ARN AD081223033238B dated 27.12.2023 submitted by the taxable person (claimant) was pending for verification.

4.2. On examination it was found that the claimant, had made reversal of ITC amounting to Rs.91,508 voluntarily **for the year 2022-23** through the said DRC-03 by debiting both the Electronic Credit Ledger and the Electronic Cash Ledger but no interest was paid despite the ITC having been utilized before reversal. On being pointed out, the taxable person deposited **interest amounting to Rs.13,839/- through DRC-03 ARN AD080224009531I dated 12.02.2024.**

5.1. The refund claim was returned with a deficiency memo stating that no document in support of the reason for claimfor refund was submitted with the claim.

5.2. Accordingly, the taxable person again filed claim for refund of unutilised balance of IGST (penalty) amounting to Rs.69,230/- lying in the Electronic Cash Ledger vide FORM GST RFD-01 ARN AA080224047360L dated 13.02.2024 showing the reason as "amount was required to be paid in temporary ID 062400000352TMP but it was wrongly deposited in this GSTIN details of which is attached herewith."

5.3. Perusal of the supporting documents attached with the claim revealed that the taxable person had deposited penalty under section 129 of the CGST Act, 2017 against the seizure of goods in transit which were intercepted without e-way bill. However, subsequently the penalty was levied from a temporary ID created for the purpose instead of being levied from the said taxable person.

6.1. From perusal of documents attached with the claim it was observed that on 28.01.2024 aconveyance carrying "Cow Chain" of HSN 7315cleared by the taxable person, M/s Anushree Industries (Proprietor: Kritika Gupta, Neemrana; GSTIN: 08DMWPG7237N1Z3) without e-way bill was intercepted by the GST authorities somewhere in the State of Haryana. Details of the goods as per bills raised by the taxable person are as follows:-

Invoice	**Quantity Kgs**	**Rate per Kg**	**Taxable Value**	**Destination**	**Tax Type**	**Amount of Tax (18%)**
493/27.01.24	1550	50	77500	Rajasthan (06)	CGST + SGST	13950
495/27.01.24	780	50	39000	Haryana (08)	CGST + SGST	7020

6.2. From perusal of the Order of Demand of Tax and Penalty in FORM GST MOV-09 dated 02.02.2024 it comes out that as against the quantity of 2,330 Kgs. declared in the two invoices,the Truck bearing registration numberRJ13GB5681 was carrying aggregate quantity of 2,775 Kgs. Further, as against the market rate of Rs.69.30 per kg, the taxable person had charged the price at the rate ofRs.50 per Kg. in the invoice. Thus, it was a case of evasion of tax both in terms of valuation of the supplies as well as supply of excess quantity without recording the same in the invoices. After taking into account the excess quantity and applying the price at an approximate rate of Rs.70/- per Kg., the tax payable was calculated and a penalty of Rs.69,230/- [which is equal to twice the tax (IGST) payable (Rs.34,615/-)] was imposed under section 129(1)(a) of the CGST Act, 2017vide Order dated 02.02.2024 in FORM GT MOV-09 upon a temporary ID No. 062400000352TMP created for one Kritika Gupta ofStation Road, Alwar who is the proprietor of the taxable person, M/s Anushree Industries, a registered supplier of the goods. Upon payment of penalty by the temporary ID the seized goods were released.

7. Facts of the case as emerging from the relevant documents are as follows:-

(i) The matter also involvessupply of goods in contravention of the provisions of the Act with intent to evade taxand, therefore, the provisions of section 130 of the CGST Act, 2017 are also attracted in the case;

(ii) As against the total tax liability of Rs.34,615/- the taxable person hadraised invoices for and paid tax amounting to Rs.20,970/- only.

(iii) As against the actual quantity of 2,775 Kg.being transported, invoices(two) were raised for aggregate quantity of 2,330 Kg only. Further, the quantity of goods recorded in the invoices was also undervalued.

(iv) Differential tax amounting to Rs.13,645/- was required to be recoveredfrom the taxable person. But the goods were released on payment of penalty only and the differential tax evaded was not recovered.

(v) Invoices raised by the registered supplier, M/s Anushree Industries (Proprietor: Kritika Gupta), Neemrana (GSTIN: 08DMWPG7237N1Z3) were taken on record of the proceedings and tax liability was also calculated on that basis. However, penalty has not been imposed upon the said registered supplier rather a temporary ID No. 062400000352TMP was created for Kritika Gupta who paid the penalty.

8. In view of the provisions of section 129 and 130 of the CGST Act, 2017 read with the relevant circulars issued by CBIC, especiallyCircular No.41/15/2018-GST, dated 13.04.2018 as amended, the correct course of action in a case involving evasion of tax by under-valuation or short-declaration of quantity in the invoice should be as follows:-

(i) If the person claiming ownership of the goods is a registered supplier already having GSTIN and invoice raised by him is also on record, proceedings should be initiated against him and temporary ID should not be created as advised in **Para-2(u) of CBIC Circular NO.41/15/2018-GST, dated 13.04.2018.**

(ii) Section 129(1)(a) of the CGST Act, 2017 provides for payment of penalty equal to two hundred percent of tax payable on such goods only if owner of the goods comes forward to pay the penalty. If the owner of goods is a registered supplier who has issued the invoices, the **temporary ID will be considered to be a distinct person in terms of section 24(5) of the CGST Act, 2017**. Thus, the temporary ID created for payment of penalty will make the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 129 ibid inapplicable to the case.

(iii) Where it comes out from the invoices submitted on record of the proceedings that movement of goods is being effected by the registered supplier in contravention of the provisions of the CGST Act, 2017 **with intent to evade payment of tax, notice in FORM GST MOV-10 proposing confiscation of the goods and conveyance should be issued** under section 130 of the CGST Act, 2017as clarified vide Para-2(l) of CBIC's Circular No.41/15/2018-GST, dated 13.04.2018**.**

(iv) Where, at the initial stage of detection, the proper officer is of the opinion that movement of goods is being effected to evade payment of tax (cases involving

under-valuation and supply of goods not recorded in the invoice), he may **directly invoke section 130 of the CGST Act, 2017 proposing confiscation in the notice in FORM GST MOV-10**.

(v) Section 129(1)(a) of the CGST Act, 2017 provides for penalty equal to two hundred percent of the tax payable for release of the intercepted goods whereas section 130 of the CGST Act, 2017 provides for levy of **fine equal to market value of goods less the tax chargeable thereon besides imposition of penalty in terms of section 122 of the CGST Act, 2017**. Thus, cases involving intent to evade payment of tax attract higher payment in terms of fine and penalty as compared to the amount of penalty payable in terms of section 129 of the CGST Act, 2017.

(vi) Section 129 and section 130 of the CGST Act, 2017 contain provisions governing levy of fine and/ or imposition of penalty only. Therefore, in cases involvingevasion of tax by way of under-valuation or supply of quantity not recorded in invoice, the proper officer should also recover the amount of tax evadedbefore proceeding to release the goods on payment of penalty.

(vii) If movement of goods by a registered supplier also involves evasion of tax by way of under-valuation and/ or quantity not recorded in the invoice and if such goods are released after recovery of penalty from a temporary ID without recovering the amount of tax evaded, it would be difficult to recover the tax evaded from the registered supplier at a subsequent point of time as no case has been booked against the GSTIN (of the registered supplier) who had issued the invoices and caused movement of goods involving evasion of tax.

9. However, in the instant case tax amounting to Rs.13,645/- has since been recovered alongwith interest and penalty equal to 15% of tax from the registered supplier vide DRC-03 ARN AD080724000525A dated 02.07.2024 as the matter had come to notice through the claim for refund.

10. Thus, while dealing with cases of detention of goods in movement it should be ensured that section 130 of the CGST Act, 2017 is applied in deserving cases proposing confiscation of goods and tax not paid is recovered from the supplier alongwith penalty in terms of section 122 of the CGST Act, 2017. Besides temporary ID should not be created if the registered supplier of the goods issuing the invoices has come forward to pay the penalty for release of the goods detained/ seized in transit.

****

(The write-up is simply intended to share the personal experience of the writer with the colleagues and the views expressed therein may not necessarily represent the stand taken by him on the provisions of law in his official capacity.)